भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1161
उत्तर देने की तारीख-10/12/2025

उच्च शिक्षा में नामांकन और एनईपी 2020 का कार्यान्वयन

1161 **श्री कपिल सिब्बल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में नामांकन अनुपात कितना है;
(ख) 2025 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों में कितनी नई सीटें सृजित की गई हैं; और
(ग) ऑनलाइन अभिगम पहुँच के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार**)**

(क) से (ग): शिक्षा मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए)' का कार्यान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य निर्धारित मानकों और मानदंडों के अनुरूप रहकर अपनी गुणवत्ता में सुधार हेतु राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के अंतर्गत बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय घटक के तहत प्रत्येक 35 विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है।

एमईआरयू विश्वविद्यालयों को 44 अनिवार्य गतिविधियों को संचालित करने के लिए निधि प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी एचईआई में शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग; अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठों की स्थापना; अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एकल-खिड़की कार्यालय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय की स्थापना; राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा (एनसीआरएफ़) और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) को वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रणाली के साथ लागू करना; अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को अपनाना; ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और स्वयं/एमओओसी जैसे ऑनलाइन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना; भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम प्रदान करना; पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणालियों (आईकेएस) को समाहित

करना; तथा 21वीं सदी के कौशल विकसित करने हेतु प्रशिक्षण देना आदि सहित शिक्षा तक पहुँच, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ाना है।

इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छात्रावासों, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों, प्रयोगशालाओं तथा उच्च शिक्षा में पहुँच और गुणवत्ता सुधार के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं का निर्माण सहित अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2020-21 में 27.3%, वर्ष 2021-22 में 28.4% तथा वर्ष 2022-23 (अस्थायी) में 29.5% दर्ज किया गया है। एआईएसएचई 2022-23 (अस्थायी) के अनुसार वर्ष 2014-15 की तुलना में विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों और महाविद्यालयों की संख्या क्रमशः 760 से बढ़कर 1213 तथा 38,498 से बढ़कर 46,624 हो गई है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विश्वविद्यालयों (इग्नू सहित) की संख्या 40 से बढ़कर 48, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की संख्या 16 से बढ़कर 23, भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) की संख्या 13 से बढ़कर 21 तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) की संख्या (वर्ष 2022-23 में 2014-15 की तुलना में) 9 से बढ़कर 25 हो गई है।

उच्चत्तर शिक्षा में नामांकन वर्ष 2014-15 के 3.42 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया है, जिसमें महिला नामांकन 1.57 करोड़ से बढ़कर 2.18 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के 46.07 लाख की तुलना में वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति छात्रों का नामांकन 69.13 लाख है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों का नामांकन वर्ष 2014-15 के 16.41 लाख से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 28.72 लाख हो गया है। बजट भाषण 2025-26 में वर्ष 2014 के बाद शुरू किए गए पाँच आईआईटी में अतिरिक्त 6,500 छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने हेतु अतिरिक्त अवसंरचना निर्माण करने की घोषणा की गई है। तदनुसार, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2025 में आयोजित अपनी बैठक में 11,828.79 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय के साथ आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरुपति), केरल (आईआईटी पलक्कड), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू एवं कश्मीर (आईआईटी जम्मू) तथा कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसंधान पार्क के निर्माण सहित पाँच नए आईआईटी के शैक्षणिक एवं अवसंरचना क्षमता विस्तार को स्वीकृति दी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को दूर करने और ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। यूजीसी ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 27 स्वयं गैर-प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर एमओओसी को हिंदी, मराठी, बांग्ला, तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया है। अनूदित सामग्री का विवरण http://www.ugceresources.in पर उपलब्ध है। यूजीसी ई-रिसोर्स पोर्टल, ई-पीजी पाठशाला से ई-सामग्री तथा यूजीसी एमओओसी पोर्टल को digitalseva.csc.gov.in के साथ एकीकृत किया गया है। यह मंच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेयटी) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के माध्यम से पहुँच सुनिश्चित करने के लिए संचालित किया जाता है।

*****